

24.10.23

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित।

आदेश

आवेदिका सुशीला देवी पति नन्दलाल यादव सा०
द्वारपट्टी, धाना-बिरनी, जिला गिरिडीह के
आवेदन पर धाना प्रभाती बिरनी के जौंच प्रमो०
के आलोक में मौजा-द्वारपट्टी, धाना-बिरनी
जिला गिरिडीह के रवाता सं. 22 प्लॉट नं. 230
रकबा 23 बी० मध्ये 2.1 बी० भूमि जिसकी चौंछ्दी
30 नीज द० रास्ता पू० नीज के गुलदयाल
कुम्हार प० नीज रांड पर द.प्र.सं. की धारा
144 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया।
दिनांक 26/8/23 को उक्त आशय का नोटिस
निर्गत करते हुए उभय पक्ष को उक्त जमीन
पर जाने अथवा कोई कार्य करने से न-
प्रतिबंधित किया गया। उभय पक्ष से कारण
सुद्धा न-की गई।

उभय पक्ष विभिन्न तिथियों को
न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-
अपना लिखित कारण वृद्धा प्रस्तुत किए।
अभिलेख में उपलब्ध प्रथम पक्ष के आवेदन,
प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण वृद्धा का
अवलोकन किया। प्रथम पक्ष का कहना है कि
विवादित भूमि उनकी खरीदगी भूमि है जो
उन्होंने केवाला सं. 1160 दिनांक 07/9/21 द्वारा
खरीदा है। आगे उनका यह न-कहना है कि
उक्त भूमि का दायित्व खारिज करवा कर वह
लगान रसीद न-प्राप्त करली चली आ रही है
साथ ही विपरीत उक्त भूमि पर जबरन कब्जा
करना चाहते हैं। अपने दावे के समर्थन में
प्रथम पक्ष केवाला की दायी प्रति तथा लगान
रसीद की दायी प्रति प्रस्तुत करते हैं।

जा.प.

प्रथम पक्ष अपने कारण पृच्छा में यह भी कहते हैं कि द्वितीय पक्ष के द्वारा उनके पति से सादे कागज पर हस्ताक्षर लेकर फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया है तथा उक्त फर्जीवाड़े को लेकर उनके पति ने द्वितीय पक्ष के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी गिरिडीह के न्यायालय में परिवाद पत्र 6967/2023 भी दाखल किया है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर जमीन में विवाद उत्पन्न कर रहा है।

वही दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का अपनी सिद्धित कारण पृच्छा में कहना है कि प्रथम पक्ष के पति ने दो एग्रीमेंट के जरिए उन्हें विवादित भूमि तथा अन्य भूमि बिक्री किया है तथा कुल 13,35,000/- (तेरह लाख पैंतीस हजार रु.) भी लिया है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि निबंधन नहीं करने के लिए प्रथम पक्ष के द्वारा युवा मुकदमा दाखल किया गया है। उनका आगे यह भी कहना है कि जमीन पर उनका दावला कब्जा है तथा उन्होंने उस पर मकान भी बनवाया है।

अभिलेख में उपलब्ध प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा, अंचल अधिकारी किल्ली का जॉय प्रतिवेदन, थाना प्रभारी किल्ली का जॉय प्रतिवेदन, प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित केवाला तथा रसीद इत्यादि की दाया प्रति, द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित रुकसारनामा की दाया प्रति का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उक्त भूमि पर हक-हकिमत तथा लेंन-देन से संबंधित विवाद है। जिसका निपटारा द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत संभव नहीं है।

आदी

अतः उक्त वाद में किसी पक्ष के हित में कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है।
उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय में अपना-अपना दावा प्रस्तुत कर विवाद का निपटारा कर लें। तब तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे।

उक्त आशय के साथ द.प्र.सं. की धारा 144(4) के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लैरकापित एवं संशोधित

24.10.23
अनुमंडल दंडाधिकारी
बगौदा-सरिया

24.10.23
अनुमंडल पदाधिका-
बगौदा-सरिया